

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 24, बुधवार, शके 1945-जून 14, 2023 Jyaistha 24, Wednesday, Saka 1945- June 14, 2023	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी

अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013

की धारा 4(1)

अधिसूचना

जयपुर, जून 13, 2023

संख्या 692 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार कोटा-लाखेरी-सवाई माधोपुर-लालसोट-दौसा मेगा हाइवे पर मेज नदी पर पापड़ी गांव के समीप हाई लेवल ब्रिज (एचएलबी) निर्माण, विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला बूंदी की तहसील इन्द्रगढ़ के निम्न गांव में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र० स०	जिला	तहसील	गांव
१	बूंदी	इंद्रगढ़	पापड़ी
२	बूंदी	इंद्रगढ़	नयागांव

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास समिति नया रलावता, पोस्ट-गरुडवासी तह. चाकसू जिला -जयपुर (राजस्थान) 303901 एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- 1.संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
- 2.प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों को समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. पी.पी.पी. माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।
6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण /सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र : -

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

अधिशायी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड लाखेरी-बूंदी

फोन नं. 9462111122

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

सामाजिक आर्थिक विकास समिति

1. श्री भरत लाल मीना (परियोजना निदेशक)

सम्पर्क नं.- 09414228071

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।